सात *HeforeJ.M.T*ndifa,J.*

चंदगी और *एक अन्य, वादी-अपीलकर्ता।*

बनाम

निहाल सिंह और *अन्य, प्रतिवादी-उत्तरदाता।*

आदेश सं2008 से दूसरी अपील।7 1976 को।

23 जनवरी, 1979।

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIII) - धारा 13 - सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र निषिद्ध है - इस तरह की रोक - चाहे अपील पर लागू हो।

और रूप पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 13 सिर्फ मुकदमों पर रोक नहीं लगाती है। यह विशेष रूप से सिविल न्यायालयों पर लागू किया जाता है क्योंकि उन्हें किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने से रोक दिया गया है कि क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार या हित अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या नहीं। अधिनियम की धारा 13 सिविल कोर्ट पर लागू होती है। ट्रायल कोर्ट की डिक्री के खिलाफ अपील की सुनवाई करने वाली अपीलीय अदालत एक सिविल कोर्ट है। यदि अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आता है, तो सिविल न्यायालय होने के नाते अपीलीय न्यायालय को उस मुद्दे पर निर्णय लेने से रोक दिया जाता है। (पैरा 12 और 13)।

हिसार के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश श्री रमेश चंद जैन, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ न्यायालय के दिनांक 12 फरवरी, 1976 के आदेश से दूसरी अपील, जिसमें श्री डीडी यादव, उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, हांसी के दिनांक 21 अप्रैल, *1973 के आदेश को उलट दिया गया है , जिसमें कहा गया है कि अपील के तहत निर्णय और डिक्री अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और निर्देश दिया गया है कि वर्तमान विवाद को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को, जिसका उस गांव में अधिकार क्षेत्र है जहां विवादित संपत्ति स्थित है (यह राय देना कि केवल यह तथ्य कि मुकदमे निषेधाज्ञा के लिए हैं भी परिणामी है क्योंकि धारा - ^ 13 (ए) और* 13 (बी) *पर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों और अन्य मुकदमों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि वादी पहली कक्षा के सहायक कलेक्टर के समक्ष नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। ग्रेड जिसके पास उस गांव में अधिकार क्षेत्र है जहां विवाद में संपत्ति धारा* 13-बी के संदर्भ में स्थित है, *यदि ऐसा सलाह दी जाती है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।*

आठ अपीलकर्ताओं *की ओर से एस. गुप्ता, एडवोकेट और आर. सी. धैया, एडवोकेट।*

नौ एस बाली, वकील, *उत्तरदाताओं के लिए।*

जे . *एम. टंडन, जे.*

एक. यह आदेश दो अपीलों का निपटारा करेगा, 1976 के एसएओ नंबर 7 चंदगी *और एक अन्य* वी। *निहाल सिंह और अन्य और* 1976 के एसएओ नंबर 8 *सरदार सिंह और एक अन्य* वी। *निहाल सिंह और अन्य,* तथ्य *और कानून के समान बिंदुओं से* जुड़े हैं।

दो. दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं ने प्रत्येक मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके गांव ढंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार में, उनके घरों के बगल में एक चौक (खाली जगह) था और इसका उपयोग गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जैसे कि बच्चों के लिए खेल का मैदान और आराम करना ।जीवधारी। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, जो दो अपीलों में समान हैं, गांव के सरपंच के साथ मिलकर इसका अतिक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को चौक पर कोई भी अतिक्रमण करने से रोका जाए।

तीन. मुकदमे का प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा विरोध किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन मुद्दों को तैयार किया, जिनमें से मुद्दे संख्या 1 और 6 में लिखा गया है: –

(एक) क्या यह भूमि ग्रामीणों की साझी संपत्ति है? यदि हां, तो किस प्रभाव तक?

(छः) क्या सिविल कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?

अंक संख्या 1 के तहत पाया गया कि चौक गांव की साझा संपत्ति है। मुद्दा संख्या 6 भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में पाया गया। नतीजतन ट्रायल कोर्ट ने 21 अप्रैल, 1973 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ अपीलकर्ताओं के पक्ष में दो मुकदमों का फैसला सुनाया।

चार. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने 21 अप्रैल, 1973 को उनके खिलाफ पारित दो फरमानों के खिलाफ 30 सितंबर, 1974 को दो अपीलों को प्राथमिकता दी। वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, हिसार ने 12 फरवरी, 1976 के अपने समेकित आदेश में अंक संख्या 6 के तहत कहा कि पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 13 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सिविल कोर्ट के पास मुकदमों की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न यह है कि विवाद में खाली स्थान पंचायत में निहित है या नहीं। यह अपील मुकदमे की एक कड़ी थी और अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रभावित हुई थी। वही

वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने पाया कि इस मुद्दे पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, जिसके पास उस गांव में अधिकार क्षेत्र है जहां विवाद में संपत्ति स्थित है। यह अपीलकर्ताओं पर छोड़ दिया गया था कि वे उनके समक्ष नए सिरे से कार्यवाही शुरू करें। इस प्रकार अपील के तहत निर्णय ो और आदेशों को अधिकार क्षेत्र में मुद्रित किया गया था। अपीलों को इन शर्तों में निपटाने का आदेश दिया गया था, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, अपील के तहत निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया था और वादी-अपीलकर्ताओं के मुकदमे खारिज कर दिए गए थे। यह वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के इन दो आदेशों के खिलाफ है कि वर्तमान अपील ो को निर्देशित किया जाता है।

पाँच. 12 नवम्बर, 1974 को लागू हुए 1974 के अधिनियम सं 1974 *के तहत अधिनियम की धारा>113 ख* में कहा गया है कि -

"किसी भी सिविल कोर्ट के पास इस अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

अमर नाथ और अन्य बनाम *ग्राम पंचायत आदि, (1) में यह व्यवस्था दी गई थी कि जहां शामिल प्रश्न शीर्षक का था, अर्थात् भूमि का कोई विशेष टुकड़ा* शामिलत देह है और ग्राम पंचायत में निहित है या नहीं, इसका निर्णय केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमान मामलों में इस अनुपात को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि उनमें शीर्षक का प्रश्न शामिल था और सिविल कोर्ट के पास अधिनियम की पुरानी धारा 13 के तहत उन्हें तय करने का अधिकार क्षेत्र था। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमों में शीर्षक का सवाल शामिल नहीं था और इसलिए, अधिनियम की पुरानी धारा 13 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी गई थी। इस तर्क में दम है। अपीलकर्ताओं ने अपने मुकदमों में दावा किया कि; विवाद में चौक का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जबकि उत्तरदाताओं ने रुख अपनाया कि यह उनकी निजी संपत्ति थी। वे चौक के शीर्षक पर मुद्दे में शामिल हो गए। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह प्रतिवादियों की निजी संपत्ति नहीं थी और इसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह विवादित नहीं है कि चौक का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किए जाने की स्थिति में, यह अधिनियम की धारा 2 (जी) में दी गई '*शमिलात देह*' की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा और इसकी धारा 4 के तहत पंचायत में निहित होगा। 1974 का संशोधन अधिनियम संख्या 34, जिसने अधिनियम की धारा 13 को प्रतिस्थापित किया, 12 नवंबर, 1974 को लागू हुआ। नतीजतन ट्रायल कोर्ट को 21 अप्रैल, 1973 को डिक्री पारित करने का अधिकार था। प्रतिवादियों ने 30 सितंबर, 1974 को ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील दायर की।

(1) 1967 करी। एल.जे. 548.

छः. 1974 के अधिनियम संख्या 34 ने धारा 13 को प्रतिस्थापित किया और अधिनियम में धारा 13-बी को जोड़ा, जो निम्नानुसार है: -

"13. क्षेत्राधिकार की पट्टी - किसी भी सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा: -

(अ) इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार या हित किसी पंचायत में निहित है या नहीं, इस संबंध में किसी प्रश्न पर विचार करना या निर्णय करना; नहीं तो

(आ) किसी अन्य मामले के संबंध में जिसे किसी अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित करने का अधिकार है; नहीं तो

(इ) इस अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या तय किए गए किसी भी मामले की वैधता पर सवाल उठाना।

13B. लंबित मुकदमों का स्थानांतरण और नई कार्यवाहियां शुरू करना :-

किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय में लंबित सभी मुकदमे, जिसमें धारा 2 के खंड (जी) के तहत या पंचायत के खिलाफ धारा 4 की उप-धारा (3) में उल्लिखित किसी भी आधार पर *शमीलत देह* से बाहर किए जाने के आधार पर राहत का दावा किया गया है , को स्थानांतरित किया जाएगा। और उपर्युक्त आधारों पर राहत प्राप्त करने के लिए नई कार्यवाही उस गांव में क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के समक्ष शुरू की जाएगी, जिसमें भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है, जो धारा 13-ए की उप-धाराओं (5) एआई डी (7) में निर्धारित तरीके से इसका निपटान करेगा।

सात. विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त "सिविल न्यायालय" शब्द में अपीलीय न्यायालय शामिल होगा या नहीं। दूसरे शब्दों में, क्या अधिनियम की धारा 13 अपीलों पर लागू होगी या नहीं। : '

आठ. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 13 में अपील ोें पर कोई लागू नहीं है और यह है

पहली बार की अदालत तक ही सीमित है। धारा 13 में यह विशेष रूप से प्रावधान नहीं है कि यह अपील पर लागू होगा। अपीलीय न्यायालय का कार्य केवल यह देखना है कि वह कौन सा आदेश था जिसे पहली बार न्यायालय को पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन होने पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित इंट्रा-वाइरल डिक्री अधिनियम की धारा 13 से मुक्त रहेगी। एक अन्य तर्क यह है कि एक अपील अधिनियम की धारा 13 बी के संदर्भ में मुकदमे की निरंतरता नहीं है। यह करनाल *सहकारी किसान सोसाइटी लिमिटेड, पिहोवा बनाम करनाल में आयोजित किया गया* है। *ग्राम पंचायत, पिहोवा और अन्य,* (2)। नतीजतन, अपील ोें को उस धारा के तहत पहली कक्षा के सहायक कलेक्टर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह निष्कर्ष कि धारा 13 अपीलों पर भी लागू होती है, प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को अपील ोें के हस्तांतरण के समान होगा और ऐसा नहीं हो सकता है।

(नौ) ठाकुर माधो सिंह और एक अन्य *पर रालियांस लगाया गया* है। *लेफ्टिनेंट जेम्स आर आर स्किनर और अन्य, (3) और (भाई) किरपा सिंह बनाम नागलीदार अजयपाल सिंह और अन्य, (4)*। *ठाकुर माधो सिंह के* मामले (सुप्रा) में यह माना गया था कि एक व्यक्ति ट्रायल कोर्ट द्वारा पूर्व-अनुभव वाद में डिक्री पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी स्थिति में सुधार करके पूर्व-विरोधी के अधिकार को हरा सकता है, क्योंकि पार्टियों के अधिकारों पर अकेले ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है और अपील की अदालत का कार्य केवल यह देखना है कि वह डिक्री क्या थी जो पहली बार अदालत ने की थी। बीत जाना चाहिए था। इस प्राधिकरण के अनुपात का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है। इस मामले में निर्णय का मुद्दा यह है कि यदि अपीलीय न्यायालय, ट्रायल कोर्ट की डिक्री के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए, एक सिविल कोर्ट या एनपीटी है। ठाकुर *माधो सिंह के मामले* (सुप्रा) में यह बिंदु न तो विचाराधीन *था और न ही इस पर विचार किया* गया था । *(भाई) किरपा सिंह के मामले* (सुप्रा) में, उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों पर सिख गुरुद्वारा अधिनियम (1925 का पंजाब अधिनियम 8) के प्रभाव पर विचार किया गया और यह पाया गया कि इसकी धारा 32 में निर्धारित प्रक्रिया पहली बार अदालत में लंबित "मुकदमों" या "कार्यवाही" पर लागू होती है और लंबित अपील को नियंत्रित नहीं करती है, भले ही उस धारा में उल्लिखित सभी या कुछ मामले उत्पन्न हों। अपील में निर्णय के लिए। यह प्राधिकरण अभी विचाराधीन मुद्दे पर फिर से ध्यान नहीं दे रहा है। धारा 13 को सिविल कोर्ट पर लागू किया गया है, न कि "मुकदमे" या "कार्यवाही" पर।

(दो) 1976 पी.एल.जे.
(तीन) 1941 लाहौर 433
(चार) ए.आई.आर. 1928 लाहौर 627.

(दस) *लाई सिंह और एक अन्य* **वी।** *ग्राम सभा नेजा दल्ला कलां और* ***अन्य,*** **(5), इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राम सभा नेजा दल्ला कलां ने तीन व्यक्तियों और वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया और प्रार्थना की कि उन्हें विवादित भूमि पर कीकर के पेड़ों को हटाने से रोका जाए। प्रतिवादियों ने दलील दी कि जमीन वक्फ बोर्ड में निहित है, न कि ग्राम सभा में। ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई, 1972 को मुकदमा खारिज कर दिया। ग्राम सभा ने एक अपील को प्राथमिकता दी और यह 12 नवंबर, 1974 को 1974 का अधिनियम संख्या 34 लागू होने पर लंबित था। अपीलीय अदालत ने कहा कि उसे इस सवाल पर फैसला करना होगा कि विवादित भूमि और उस पर पेड़ वादी में निहित हैं या नहीं। ग्राम सभा और 1974 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 13 ने सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस तरह के किसी भी निर्णय लेने से रोक दिया। धारा 13 में दिखाई देने वाले "सिविल कोर्ट" शब्द का अर्थ अपीलीय न्यायालय भी है। यह महत्वपूर्ण था कि धारा 13 में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि मूल क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और दूसरी ओर यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अपील को स्वीकार कर लिया गया था और ट्रायल कोर्ट की डिक्री को अधिकार क्षेत्र के बिना आयोजित किया गया था। यह भी निर्देश दिया गया कि विवाद की कार्यवाही पहली कक्षा के सहायक कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी, जिसके पास अधिनियम की धारा 13 बी के संदर्भ में गांव नेजा दल्ला कलां पर अधिकार क्षेत्र है। प्रतिवादियों ने 1976 के आरएसए नंबर 768 दायर किया और 3 मार्च, 1977 को इसका फैसला किया गया। उन्होंने प्रथम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी कि अधिनियम की धारा 13 के मद्देनजर सिविल कोर्ट के पास स्पष्ट रूप से मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनकी शिकायत थी कि धारा 13 बी लागू नहीं होती है और निचली अदालत के डिक्री को अधिकार क्षेत्र के बिना पाए जाने के बाद निचली अपीलीय अदालत को वादी यानी ग्राम सभा नेजा दल्ला कलां को वादी को वापस करने का आदेश देना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और प्रथम अपीलीय न्यायालय को ग्राम सभा को वाद वापस करने का निर्देश दिया गया। इस निर्णय में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई थी कि "सिविल न्यायालय" शब्द अपीलीय न्यायालय को भी कवर करता है और इसे उच्च न्यायालय में बनाए रखा गया था।**

(ग्यारह) **अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 13 का आयात यह है कि क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार या ब्याज इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या नहीं, इस बारे में किसी भी सवाल से जुड़े मुकदमे प्रतिबंधित हैं। एक**

(5) 11977 पी.एल.जे. : 266.

टन

अपील मुकदमे की निरंतरता नहीं है और इसलिए, एक अलग स्तर पर खड़ा है। इसलिए, अधिनियम की धारा 13 को अपील ो पर लागू नहीं किया जा सकता है। तर्क में कोई दम नहीं है और यह भ्रामक धारणा पर भी आधारित है। धारा 13 अकेले मुकदमों पर रोक नहीं लगाती है। यह विशेष रूप से सिविल न्यायालयों पर लागू किया गया है क्योंकि उन्हें किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने से रोक दिया गया है कि क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार या हित अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या नहीं। अपील वाद की एक कड़ी है और यह *करनाल सहकारी किसान सोसायटी लिमिटेड, पिहोवा बनाम ग्राम पंचायत, पिहोवा और अन्य* में आयोजित की गई थी । आगे यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 13 बी के संदर्भ में अपील को शामिल करने के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, अधिनियम की धारा 13 बी के निहितार्थ मुद्दे के अधीन नहीं हैं। अन्यथा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 13 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकती है, यह मुद्दा कि अपील वाद की निरंतरता है या नहीं, सभी प्रासंगिकता खो देता है।

(बारह) अधिनियम की धारा 13 सिविल न्यायालय पर लागू होती है। ट्रायल कोर्ट की डिक्री के खिलाफ अपील की सुनवाई करने वाला अपीलीय न्यायालय एक सिविल कोर्ट है। निचली अपीलीय अदालत के समक्ष विचाराधीन मुद्दा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आता है। दीवानी न्यायालय होने के नाते अपीलीय न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने से रोक दिया गया है। इन परिस्थितियों में, निचली अपीलीय अदालत का यह मानना सही था कि अपीलें भी अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रभावित हुई थीं और इसके परिणामस्वरूप अपीलों के तहत डिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से परे था और पीड़ित पक्ष को उचित मंच से उपाय प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया गया था।

(तेरह) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं और लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

एस.सी.के.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा

टन